नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 090
दि. 01.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कलीना की सियासत में 'नगीना' कौन बनेगा? टूटते गठबंधन बिखरता जनाधार और बीएमसी चुनाव की असली कसौटी

मुंबई। मुंबई की उत्तर भारतीय बहुल कलीना विधानसभा सीट एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ खड़ी हुई है। जैसे-जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे यहां का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिस कलीना ने पिछले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की एकजुटता का फायदा देखा था, वही क्षेत्र अब उसी गठबंधन के भीतर उभरे मतभेदों और प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस, जो विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थीं, अब नगर निगम चुनाव में आमने-सामने हैं। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने न सिर्फ स्थानीय समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि इस बार कलीना का 'नगीना' कौन होगा।

पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की मजबूती ने उद्धव सेना के उम्मीदवार संजय पोटनीस के लिए राह आसान कर दी थी। कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक और शिवसेना का मराठी आधार एक साथ आने से विरोधियों के लिए चुनौती बढ़ गई थी। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के अलग मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। कलीना में करीब 24 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जो अब एकतरफा किसी एक दल के साथ जाती नहीं दिख रही। यही नहीं, लगभग 15 प्रतिशत उत्तर भारतीय मतदाता भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तर भारतीय वोटर पारंपरिक रूप से मुद्दों और उम्मीदवार की पकड़ के आधार पर मतदान करता रहा है, ऐसे में सभी दलों ने अपने-अपने उत्तर भारतीय नेताओं को आगे कर दिया है। नतीजतन, कलीना की गलियों, झोपड़पट्टियों और हाउसिंग सोसाइटियों में राजनीतिक

गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं।

कलीना का चुनावी चरित्र हमेशा से बहुस्तरीय और जटिल रहा है। यह क्षेत्र केवल एक समुदाय या एक वर्ग पर निर्भर नहीं करता। यहां लगभग 37 प्रतिशत मराठी मतदाता हैं, जो शिवसेना की पारंपरिक ताकत माने जाते हैं। इसके साथ 24 प्रतिशत मुस्लिम, 15 प्रतिशत उत्तर भारतीय, करीब 8.5 प्रतिशत क्रिश्चियन और लगभग 10 प्रतिशत गुजराती, मारवाड़ी व दक्षिण भारतीय मतदाता भी हैं। यही विविधता कलीना को मुंबई की सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सीटों में शामिल करती है। 2009 में कृपाशंकर सिंह की बड़ी जीत आज भी राजनीतिक विश्लेषण का अहम उदाहरण है, जब उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटों के मजबूत गठजोड़ ने चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी। मौजूदा हालात में फिर से ऐसा कोई सामाजिक समीकरण बन पाएगा या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।

शिवसेना में हुई टूट और उसके बाद के दलबदल ने कलीना की राजनीति को और उलझा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के नगरसेवक जहां खुद को 'वफादार' साबित करने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं मनसे से आए कुछ नगरसेवक शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इससे शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में भी विभाजन की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस के दोनों पूर्व नगरसेवक फिलहाल पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन स्थानीय राजनीति में अंतिम समय में समीकरण बदलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में कलीना का चुनाव केवल स्थानीय सत्ता का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह महाविकास आघाड़ी की भविष्य की दिशा और उसकी एकता की भी अग्निपरीक्षा बन गया है।

बीएमसी चुनाव के लिए हुए नए परिसीमन और आरक्षण बदलावों ने भी कलीना को राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल दिया है। कई प्रभागों में आरक्षण की श्रेणी बदलने से पुराने दावेदारों की राह मुश्किल हो गई है और नए चेहरों के उभरने की संभावनाएं बढ़ी हैं। कहीं महिला आरक्षण के कारण अनुभवी पुरुष नेताओं को पीछे हटना पड़ा है, तो कहीं 'जनरल' सीट होने से मुकाबला बहुकोणीय और ज्यादा तीखा हो गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि इस बार चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय कामकाज, समाज के साथ उसका जुड़ाव और जमीनी पकड़ ज्यादा मायने रखेगी।

कलीना की झोपड़पट्टियों में रहने वाले मतदाता बुनियादी सुविधाओं, पुनर्विकास, पानी, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सजग हैं। वहीं मध्यमवर्गीय और शिक्षित तबका साफ-सफाई, ट्रैफिक, स्कूल-कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी अपनी भूमिका निभा रही है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन तमाम वर्गों को साधने में सफल होगा, वही आगे निकल सकता है।

कुल मिलाकर कलीना विधानसभा क्षेत्र इस बार सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र की बदलती राजनीति का आईना बन चुका है। यहां होने वाला मुकाबला यह संकेत देगा कि गठबंधन की राजनीति आगे कितनी कारगर रहने वाली है और अलग-अलग लड़ने का फैसला किसे फायदा पहुंचाता है। मुस्लिम और उत्तर भारतीय मतदाताओं का रुझान, मराठी वोटरों की दिशा और छोटे समुदायों की भूमिका—इन सभी का संतुलन ही तय करेगा कि कलीना का असली 'नगीना' कौन बनेगा। बीएमसी चुनाव में कलीना का फैसला न सिर्फ स्थानीय राजनीति, बल्कि मुंबई की सत्ता की बड़ी तस्वीर पर भी दूरगामी असर डालने वाला साबित हो सकता है।

कर्तव्य पथ पर गूंजेगा मौन वीरों का सम्मान, 26 जनवरी की परेड में पहली बार दिखेगी सेना की पशु शक्ति

नई दिल्ली। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड केवल आधुनिक हथियारों, अनुशासित टुकड़ियों और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कर्तव्य पथ पर उन "मूक योद्धाओं" को भी पूरे देश का सलाम मिलेगा, जिन्होंने बिना शब्दों के, बिना किसी श्रेय की अपेक्षा के, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना का साथ निभाया है। 26 जनवरी 2026 को होने वाली परेड में भारतीय सेना का पशु दस्ता पहली बार इतने व्यापक, संगठित और प्रतीकात्मक स्वरूप में शामिल होने जा रहा है, जो देश की रक्षा में पशुओं की ऐतिहासिक और वर्तमान भूमिका को सामने लाएगा। यह दृश्य न केवल अनोखा होगा, बल्कि भावनात्मक भी, क्योंकि इन चार पैरों वाले योद्धाओं का योगदान अक्सर परदे के पीछे रह जाता है।

इस विशेष दस्ते में दो बैक्ट्रियन ऊँट, चार ज़ांस्कर पोनी, चार शिकारी पक्षी यानी रैप्टर्स, 10 भारतीय नस्ल के सैन्य कुत्ते और पहले से सक्रिय सेवा में लगे छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल होंगे। परेड की शुरुआत बैक्ट्रियन ऊँटों से होगी, जो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना की जीवनरेखा माने जाते हैं। दो कूबड़ वाले ये दुर्लभ ऊँट 15 हजार फीट से अधिक ऊँचाई, बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में भी 250 किलो तक भार ढोने में सक्षम हैं। दुर्गम सीमाई इलाकों में जहां आधुनिक वाहन भी जवाब दे देते हैं, वहां ये ऊँट सैनिकों के लिए रसद, हथियार और जरूरी सामान पहुंचाने का भरोसेमंद साधन बने रहते हैं। परेड में उनकी मौजूदगी लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के कठिन जीवन की झलक भी होगी।

ऊँटों के बाद ज़ांस्कर पोनी कदमताल करती नजर आएंगी, जो लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल हैं। ये पोनी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी 40 से 60 किलो तक वजन लेकर लंबी दूरी तय कर सकती हैं। सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक इलाकों में ये पोनी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। बर्फीले दर्रों, संकरे पहाड़ी रास्तों और जानलेवा मौसम में जब इंसान और मशीन दोनों की परीक्षा होती है, तब यही पोनी सैनिकों के लिए जीवनदायिनी साबित होती हैं। कर्तव्य पथ पर उनका चलना दरअसल उन अनदेखे संघर्षों की कहानी कहेगा, जो रोज़ सीमा पर लड़ी जाती है।

परेड में शामिल चार शिकारी पक्षी भारतीय सेना की आधुनिक और स्मार्ट रणनीति का प्रतीक होंगे। इन रैप्टर्स का उपयोग निगरानी, सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई खतरों से निपटने के लिए किया जाता है। सीमावर्ती इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में इन पक्षियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। तकनीक और प्रकृति के इस अनूठे संयोजन ने सेना को नए विकल्प और नई ताकत दी है, जिसकी झलक पहली बार आम जनता को गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलेगी। इस दस्ते का सबसे भावुक और आकर्षक हिस्सा होंगे सैन्य कुत्ते, जिन्हें भारतीय सेना में सम्मान के साथ "मूक योद्धा" कहा जाता है। मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स में प्रशिक्षित ये कुत्ते आतंकवाद विरोधी अभियानों, विस्फोटक और हथियारों की पहचान, खोज और बचाव अभियान तथा आपदा राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार इन्हीं कुत्तों ने समय रहते खतरे को भांपकर सैनिकों और आम नागरिकों की जान बचाई है। परेड में जब ये कुत्ते अपने प्रशिक्षकों के साथ अनुशासित कदमों से गुजरेंगे, तो यह दृश्य देश को यह याद दिलाएगा कि वीरता केवल वर्दी पहनने तक सीमित नहीं होती।

आत्मनिर्भर भारत के संदेश को मजबूती देते हुए सेना अब विदेशी नस्लों के साथ-साथ भारतीय नस्लों के कुत्तों को भी बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बई और राजापलायम जैसी स्वदेशी नस्लें अपनी सहनशक्ति, बुद्धिमत्ता और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के कारण सेना की पसंद बन रही हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में इन भारतीय नस्लों की मौजूदगी न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगी, बल्कि देश की परंपरा और आधुनिकता के संतुलन को भी दर्शाएगी।

जब 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर ये ऊँट, पोनी, शिकारी पक्षी और सैन्य कुत्ते कदमताल करेंगे, तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि भारत की रक्षा केवल आधुनिक हथियारों और तकनीक से नहीं होती, बल्कि उन मूक जीवों के साहस, निष्ठा और त्याग से भी होती है, जिन्होंने सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर लद्दाख के वीरान रेगिस्तान तक चुपचाप लेकिन मजबूती से देश सेवा की है। यह परेड न केवल शक्ति का प्रदर्शन होगी, बल्कि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने मौन वीरों को दिया गया सच्चा सम्मान भी होगी।

सोमालीलैंड को इजरायली मान्यता पर तुर्की का कड़ा ऐतराज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ी भू-राजनीतिक हलचल

अंकारा। सोमालीलैंड को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के इजराइल के फैसले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तुर्की ने इस कदम का खुलकर विरोध करते हुए इसे अवैध, अस्वीकार्य और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने साफ शब्दों में कहा है कि सोमालिया की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंकारा में सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान एर्दोगन ने यह बयान देकर स्पष्ट संकेत दिया कि तुर्की इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है।

एर्दोगन ने कहा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहले ही राजनीतिक अस्थिरता, गृह संघर्ष, आतंकवाद और मानवीय संकटों से जूझ रहा है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी अलगाववादी इकाई को मान्यता देना आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल का यह फैसला न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून और

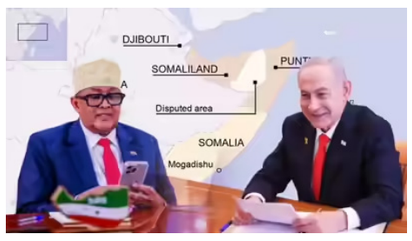

संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि इससे सोमालिया में शांति बहाली के प्रयासों को भी गहरा झटका लगेगा। तुर्की राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि हर परिस्थिति में सोमालिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना तुर्की की प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर अंकारा अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा।

तुर्की और सोमालिया के रिश्ते पिछले एक दशक में लगातार मजबूत हुए हैं। तुर्की ने सोमालिया में मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। मोगादिशु में तुर्की का सैन्य प्रशिक्षण अड्डा और विकास परियोजनाएं इस साझेदारी का प्रमाण हैं। ऐसे में सोमालीलैंड को मान्यता देने का इजरायली कदम तुर्की के लिए केवल कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि उसके रणनीतिक हितों पर सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एर्दोगन ने संकेत दिया कि तुर्की इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूती से उठाएगा और सोमालिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मामले की जड़ 1991 में जाती है, जब सोमालिया में गृह युद्ध के चलते केंद्रीय सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। उसी दौरान देश के उत्तरी हिस्से ने खुद को सोमालीलैंड के नाम से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद से सोमालीलैंड ने अपनी अलग सरकार, संसद, मुद्रा, पासपोर्ट और सशस्त्र बल विकसित कर लिए। आंतरिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर रहने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अब तक इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ लगातार इसे सोमालिया का अभिन्न हिस्सा मानते रहे हैं। इजराइल का हालिया फैसला इस स्थिति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि वह सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन साधने जैसे कारक हो सकते हैं। हालांकि, इस कदम ने न केवल तुर्की बल्कि कई अन्य मुस्लिम और अफ्रीकी देशों में भी चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें आशंका है कि इससे अफ्रीका में अलगाववादी आंदोलनों को नया बल मिल सकता है। सोमालिया की संघीय सरकार ने भी इजराइल के फैसले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। मोगादिशु का कहना है कि किसी भी देश को उसकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। तुर्की का समर्थन मिलने से सोमालिया का रुख और मजबूत हुआ है। दोनों देशों ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साझा रणनीति अपनाएंगे।

चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता से समझौता नहीं, चुनाव कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: आयोग का सख्त संदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए यह संदेश दे दिया है कि चुनाव ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को डराने-धमकाने या दबाव में लेने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) हों, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), असिस्टेंट ईआरओ या फिर चुनाव पर्यवेक्षक—सभी की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग ने यह दो टूक कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव कर्मचारियों को निर्भय वातावरण देना अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। यह सख्त रुख ऐसे समय सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बाहर आकर आयोग पर कई आरोप लगाता नजर आया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने साफ किया कि वह किसी भी तरह की धमकी, दबाव या राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित होकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे हटने वाला नहीं है।

आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि राज्य सरकार को तुरंत प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर को बढ़ा हुआ मानदेय जारी करना चाहिए, जिसे आयोग पहले ही मंजूरी दे चुका है। आयोग का कहना है कि बीएलओ चुनावी व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मतदाता सूची के अद्यतन से लेकर जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। यदि उनके अधिकारों और सुविधाओं की अनदेखी की जाती है तो इसका सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर पड़ता है। आयोग ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस दिशा में लापरवाही बरती गई तो वह सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल जैसे घनी आबादी वाले और सामाजिक रूप से विविध राज्य में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के स्वरूप में बदलाव किए जा रहे हैं। आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि ऊंची आवासीय इमारतों, गेटेड कॉलोनियों और झुग्गी-बस्तियों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े या किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आयोग का मानना है कि मतदान केंद्रों को मतदाताओं के नजदीक लाने से न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। राजनीतिक दबाव के मुद्दे पर आयोग का रुख सबसे अधिक सख्त नजर आया। आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को साफ चेतावनी दी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके जमीनी स्तर के नेता या कार्यकर्ता किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाने, डराने या प्रभावित करने की कोशिश न करें।

कटुआ में आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार, 39 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान से लेकर ड्रोन तस्करी तक पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कटुआ/जम्मू। जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती जिले कटुआ में वर्ष 2025 के दौरान पुलिस ने आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर ठगी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसने न केवल आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ी बल्कि आम लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत किया है। जिले में सक्रिय आतंकवादी ढांचे को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से चलाए गए अभियानों के तहत पुलिस ने 39 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की, जो पर्दे के पीछे रहकर आतंकियों को रसद, सूचना और शरण उपलब्ध करा रहे थे। इनमें से 18 ओजीडब्ल्यू को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लेकर जेल भेजा गया, ताकि भविष्य में वे किसी भी आतंकी गतिविधि को अंजाम न दे सकें।

कठुआ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा द्वारा जारी वार्षिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले में आतंकवाद से जुड़े चार गंभीर मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो सक्रिय आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इन अभियानों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने न केवल हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति लाइनों को ध्वस्त किया, बल्कि उन स्थानीय चेहरों को भी बेनकाब किया जो लंबे समय से आतंकियों के लिए 'स्लीपर सपोर्ट सिस्टम' के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम कदम है, क्योंकि यही लोग आतंकियों और स्थानीय आबादी के बीच सेतु बनते हैं।

आतंकवाद के साथ-साथ कठुआ पुलिस ने ड्रोन के जरिए हो रही नशा तस्करी पर भी बड़ी चोट की है। सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ गिराने के एक मामले में पुलिस ने 447 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि ड्रोन का इस्तेमाल न केवल नशा तस्करी बल्कि भविष्य में हथियारों की तस्करी के लिए भी किया जा सकता था। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क को समय रहते तोड़ना जिले की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी था। ड्रोन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों में तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है।

सिर्फ आतंकवाद और तस्करी ही नहीं, बल्कि साइबर अपराध के मोर्चे पर भी कठुआ पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब चार करोड़ रुपये की ठगी गई राशि बरामद कर पीड़ितों को वापस दिलाई। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि साइबर अपराधों में अक्सर पीड़ितों का पैसा वापस मिल पाना मुश्किल होता है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए गांवों और कस्बों में साइबर सुरक्षा से जुड़े अभियान भी चलाए, ताकि आम नागरिक डिजिटल ठगी से बच सकें।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

खानपान के संयम से स्वस्थ-सुखी जीवन

आज हम एक नये साल में प्रवेश कर रहे हैं। नववर्ष पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मंगलकामनाएं अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन नये वर्ष के आगमन के उत्साह में हम इकतीस दिसंबर को देर रात तक नये साल के जश्न में जुटे रहते हैं। इधर देश में प्रयोगधर्मी खानपान व नशीली पार्टियों का फैशन जैसा बन गया है। देर रात तक चलने वाली पार्टियों के बाद नये साल के पहले दिन ही हमारी नींद देर से खुलती है। फिर नये साल का पहला दिन ही सुस्ती और आलस्य के साथ शुरू होता है। कायदे से नये साल की शुरुआत एक ताजगीभरी सुबह के साथ होनी चाहिए। नये संकल्पों के लिए ऊर्जावान सुबह के साथ शुरू हो पहला दिन। निश्चित रूप से हमारा सामान्य जीवन व्यवहार बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए कुछ नियम जरूरी भी हैं। दरअसल, नये दौर में हम, खासकर नई पीढ़ी एक अराजक जीवन जीने को अपनी शान समझती है। अमेरिका में हुए कुछ शोधों के बाद पता चला है कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना हमारी सेहत की गारंटी होती है। यह पुरानी भारतीय अवधारणा ही है। भारतीय समाज में ब्रह्ममुहूर्त में उठने की प्रतिष्ठित परंपरा रही है। इस समय प्रकृति एकाग्रता-ध्यान हेतु शांत होती है। शरीर के मल स्वतः बाहर निकलने की प्रक्रिया में होते हैं। यह तथ्यपरक है कि हम जितनी जल्दी नित्यकर्म से निवृत्त होते हैं, उतने जल्दी स्वस्थ होते हैं। नया साल न तो कोई जादू है और न ही चमत्कार करने वाला होता है। महज एक नये दिन मानक होता है। नया दिन बदलाव के संकल्प का और उससे जीवन को सुखमय बनाने का। यूं भी जब जनवरी के पहले दिन का आगमन होता है तो शीत का प्रकोप होता है, जिसके चलते जीवन की गति मंथर हो जाती है। संभवतः शीतजनित इस नीरसता व एकरसता को तोड़ने के लिए दुनिया में नववर्ष के उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा शुरू की गई होगी।

सही मायनों में उत्सव का उल्लास हमारे तन-मन को स्वस्थ और मंगलमय बनाने के लिए होता है। लेकिन इस दौरान हम खानपान को लेकर अराजक व्यवहार करने लगते हैं। दरअसल, हमारा शरीर बेहद संवेदनशील व हमारी सेहत के प्रति सचेत होता है। शरीर का अपना उन्नत सुरक्षा-तंत्र लगातार हमारे स्वास्थ्य की फिक्र करता है। वह शरीर को सर्दी-गर्मी के अनुरूप अपना ताप नियंत्रित कर हमारे जीवन की रक्षा करता है। वह बार-बार संकेतों से हमें सचेत करता है। हम उसकी आवाज अनसुनी कर देते हैं। एक सीमा तक वह इसे बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर असहाय होने की स्थिति में बीमार पड़ जाता है। अक्सर देखते हैं कि नये साल के जश्न, शादी-विवाह व मुफ्त की पार्टियों में हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन खाने-पीने की अराजकता पेट को लगातार परेशान करती है। उत्सव व पार्टी में हम सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा खा लेते हैं। योग दर्शन बताता है कि पेट को चार भागों में मानकर दो भाग खाने के लिये, एक पानी और एक आकाश तत्व के लिये रखें। आकाश तत्व यानी खाली रखने के लिए, जिससे पाचन की क्रिया सुगम होती है। हम किसी मशीन में भी कोई पदार्थ ठूंस-ठूंस कर भर दें, तो उसकी गति बाधित होती है। फिर पेट तो कोमलअंगी होता है। जापान के एक द्वीप में सौ से अधिक उम्र के सैकड़ों लोग मौजूद है, जिसने पश्चिमी शोधकर्ताओं को चकित किया। शोध में पता चला कि श्रमशील व प्रसन्न रहने वाले इस द्वीप के लोगों की एक खास आदत है, जब उन्हें लगता है कि खान पर्याप्त हो गया है, तो वे थाली का खाना उसी वक्त छोड़ देते हैं। यही उनकी लंबी उम्र का राज भी है। दरअसल, भूख हमारी शारीरिक जरूरत से अधिक मानसिक होती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे खाने की मात्रा में कमी होनी चाहिए। हम जीने के लिये खाएं, न कि खाने के लिए जीएं। अब चाहे नये साल की पार्टी हो या कोई पर्व-त्योहार, हमें संयमित भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। हल्का, सुपाच्य व कम भोजन जहां दवा है, वहीं गरिष्ठ व अधिक भोजन हानिकारक हो सकता है।

खुद को बेहतर मनुष्य बनाने की करें नई शुरुआत

> “याद आता है, अपने वक्त के जमीर की आवाज मिर्जा गालिब ने भी उस वक्त की लगभग इसी तरह की बेबसी को इन शब्दों में व्यक्त किया था : बस-कि दुश्वार है हर काम का आसां होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसां होना।

देश का दिल कहलाने वाली राजधानी दिल्ली इन दिनों जहरीले हवा-पानी के कारण अपने शहरियों की सेहत के लिए कोरोना के बाद का सबसे बड़ा संकट झेल रही है। दिल्ली के अखबारों में छपी वर्षांत छोटी-छोटी बात में जानलेवा हिंसा की खबरें चीख-चीख कर यह जता रही हैं कि उसकी सामाजिक सेहत और भी खराब है, इतनी खराब कि उसके कई निवासियों को सहज मनुष्यता से भी महरूम कर, उन्हें मनुष्य की जगह हत्यारा बना दिया है।

लेकिन दिल्ली ही क्यों, इन्हीं अखबारों में छपी गोरखपुर की उस खबर को पढ़ लें, जिसमें ग्यारहवीं के एक छात्र को ह्वाट्सएप पर लगाये उसके एक स्टेटस से ख़फ़ा सिरफिरों ने उसके कालेज में ही गोलियों से भून डाला, तो साफ हो जाता है कि शेष देश का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। साफ कहें तो वहां की सामाजिकता भी इतने अंदेशों के हवाले है कि सिर्फ वही अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं, जो किसी की असुविधा के कारण नहीं हैं। लेकिन इस लिहाज से, इसके बावजूद, उनकी मुश्किलों का अंत बहुत मुश्किल है कि जो हालात हैं, उनमें बहुत चाहकर भी किसी की असुविधा का कारण न बनना संभव नहीं हो पा रहा। बढ़ता धार्मिक व साम्प्रदायिक विद्वेष और प्रदूषित राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं बेतरह इसके आड़े आ रही हैं।

तिस पर आम लोगों की बात करें तो वे अपने एकांत में तो अकेले हैं ही, भीड़ भरी सड़कों पर भी अकेले ही हैं। क्योंकि जब भी उनके जैसे किसी निरीह या निर्दोष पर कोई प्रहार होता है, भरी हुई सड़कें देखकर भी कुछ नहीं देखतीं। बुजदिली की शरण में चली जाती और मृत्यु से

पहले ही मर जाती हैं। माब लिंचिग जैसी वारदातों के वक्त बढ़-चढ़कर ‘बहादुरी’ प्रदर्शित करने वालों का पौरुष उस वक्त जानें कहां चला जाता है। शायद इसलिए कि उनके निकट मारना बचाने से बड़ा जीवन-मूल्य हो गया है और किसी की रक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डालने का जोखिम उन्हें इतना बड़ा लगता है कि वे उसको उठा नहीं पाते।

ऐसे में जब कभी धूमधाम से आई इक्कीसवीं शताब्दी के एक चौथाई वर्ष निःशेष होने वाले हैं और बर्फीली हवाएं ठिठुरन बनकर तन-मन को बेधे जा रही हैं, आगे मनुष्य के मनुष्य ही न रह पाने के अंदेशे जताती इन खबरों के बीच जो बात सबसे ज्यादा सताती है, वह, निस्संदेह, स्मृतिशेष वीरेन डंगवाल द्वारा अरसा पहले अपनी एक कविता में पूछे गये इस सवाल के अनुत्तरित रह जाने से पैदा हुई है : आखिर हमने कैसा समाज रच डाला है, जिसमें जो कुछ भी चमक रहा है काला है?

याद आता है, अपने वक्त के जमीर की आवाज मिर्जा गालिब ने भी उस वक्त की लगभग इसी तरह की बेबसी को इन शब्दों में व्यक्त किया था : बस-कि दुश्वार है हर काम का आसां होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसां होना।

ऐसे में यह सवाल भी बहुत स्वाभाविक है कि क्या हम अपनी मनुष्यता के लिहाज से ग़ालिब के वक्त में ही खड़े रह गये हैं? अगर नहीं तो क्यों हमारे बीच कोई इतना बेदर्द है कि इन हालात में नये साल की शुभकामनाएं देते हुए उसका कलेजा फटने को नहीं आ जाता और क्यों जगजीत सिंह की गाई इस मशहूर गजल के शायर को कहना पड़ता है कि ‘तुमको ये नया साल मुबारक हो दोस्तो, मैं जख्म गिन रहा हूं अभी पिछले साल के!’

पिछला वर्ष इस तरह कलेजा निकाल कर जायेगा तो कौन इस भ्रम के सहारे खुश हो सकता है कि इक बरहमन ने कहा है कि साल अच्छा है या कि किस्से बनेंगे अबके बरस भी कमाल के। अगर पिछले साल के ज़ख्म गिनने की विडम्बना उसका साथ नहीं छोड़ती तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मीर-ए-कारवां को यह देखने की फुर्सत है या नहीं कि वह आ रहा है पांव के कांटे निकाल के!

यहां कह सकते हैं कि 2025 ने बहुत से जख्म दिए तो छाती चौड़ी करने के अनेक मौके भी। लेकिन इस बात का क्या करें कि इससे यह गम गलत नहीं होता कि उसने हमें मनुष्यता के उदात्तीकरण की ओर ले जाने के बजाय उसके अवसान के अंदेशे ही प्रबल किये हैं। ये अंदेशे उत्सव बनते बड़े-बड़े युद्धों और उनमें निरीह बच्चों तक के संहारों में ही नहीं, हमारे निजी व सामाजिक जीवन की छोटी-छोटी कुटिलताओं में भी नजर आते हैं।

बकौल कविवर हरीशचंद्र पांडे, ‘नया साल मुबारक हो’ कहते हुए लगता है कि हम झाड़ियों के उलझाव से बाहर निकलने की कोशिश करती बैलों के गले में बंधी घंटियों में बदल गये हैं। इस खतरे की घंटी को, अभी और अभी, फौरन से पेश्तर सुने जाने की जरूरत है। इसलिए कि हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत मनुष्य के रूप में अपनी रक्षा की है। हम यह रक्षा कर पाये तो वह सब भी फिर से पाने की उम्मीद कर सकते हैं, जो पहले गंवा आये हैं। लेकिन नहीं कर पाये तो? इस सवाल का जवाब भला किसे मालूम नहीं? और किसे नहीं मालूम कि उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम नये साल में प्राणपण से अपनी मनुष्यता को बचायें और बेहतर बनायें।

प्रेरणा

कल्याण का धाम है शरीर : इंद्रिय संयम से जीवन की पूर्णता

“बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो”—महात्मा गांधी की यह शिक्षा केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध, शांत और कल्याणकारी बनाने का गहरा सूत्र है। यही बात हमारे वेदों ने भी सहस्रों वर्ष पहले कही थी—“भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः”, अर्थात हे देवों, हम अपने कानों से केवल भद्र, शुभ और कल्याणकारी बातों को ही सुनें। यह संयोग नहीं, बल्कि सनातन सत्य है कि मनुष्य का पतन या उत्थान उसके देखने, सुनने और बोलने से आरंभ होता है। शरीर को हम सामान्यतः भोग का साधन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे कल्याण का धाम है, वह क्षेत्र है जहां से साधना भी शुरू होती है और सिद्धि भी प्राप्त होती है।

दूसरों की निंदा सुनते-सुनते मनुष्य का अंतःकरण कठोर होने लगता है। धीरे-धीरे संवेदना समाप्त हो जाती है और भीतर राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। कान भी बुरी बातों को सुनने का अभ्यास बना लेते हैं। जैसे नशे का आदी व्यक्ति साधारण पेय से तृप्त नहीं होता, वैसे ही नकारात्मकता का अभ्यस्त मन शुभ और सरल बातों में रस नहीं ले पाता। चरस पीने वाले को दूसरा नशा प्रभाव नहीं करता और शराब पीने वाले को सामान्य पेय सुकून नहीं देता, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर अश्लील, कटु और दूषित बातें सुनता है, उसे शुद्ध विचार बोझ लगने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभ से ही गलत, असभ्य और विकृत बातों पर कान न दिया जाए।

वेदों का आग्रह है कि हम भद्र को सुनें। भद्र का अर्थ केवल मीठा या मनोरंजक नहीं है, बल्कि वह जो मन को विकृत न करे, जो चेतना को नीचे न गिराए, जो भीतर वासना, क्रोध और द्वेष न जगाए। भद्र वही है जो हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे। भद्र को सुनना, भद्र को देखना और भद्र को स्पर्श करना—यह त्रिवेणी है जिसके प्रवाह में जीवन पवित्र बनता है। बच्चों को यदि शुरू से ही यह सिखाया जाए कि आंख, कान और जिह्वा का उपयोग सोच-समझकर करना है, तो आगे चलकर उनके चरित्र की नींव मजबूत बनती है।

पुराने समय में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि बच्चा क्या देख रहा है। यदि कोई बालक वह देख रहा होता जिसे नहीं देखना चाहिए, तो बड़े तुरंत टोक देते थे। यह टोकना दमन नहीं, बल्कि संरक्षण था। गुरुजन और अभिभावक जानते थे कि दृष्टि का संस्कार मन को गढ़ता है। एक छोटी सी घटना इसका सुंदर उदाहरण है—गुरुजी के शिष्य के कमरे की खिड़की से सामने की गली और एक परिवार दिखाई देता था। गुरुजी कभी शिष्य को झांकते हुए नहीं देखते थे, लेकिन यदि खिड़की खुली दिख जाती, तो कठोर शब्दों में पूछते—उधर की खिड़की क्यों खुली है? उस कठोरता के पीछे करुणा और दूरदृष्टि थी। परिणाम यह हुआ कि शिष्य के भीतर ऐसी आदत बन गई कि महीनों तक वह उस ओर की खिड़की नहीं खोलता। आज भी वही संस्कार बना हुआ है। यह शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुशासन से मिली। प्रश्न यह नहीं है कि बाहर क्या है, प्रश्न यह है कि बाहर देखकर हमें क्या मिल रहा है। क्या बाहर देखने से हम वैज्ञानिक बन जाएंगे या वैरागी हो जाएंगे? यदि नहीं, तो आंखों को वहां क्यों भटकने दें? भद्र को ही देखना, भद्र को ही सुनना और भद्र को ही स्पर्श करना—यह शिक्षा यदि बाल्यावस्था से मिले, तो जीवन की दिशा स्वयं सही हो जाती है।

संत शिरोमणि डोंगरे जी का एक वाक्य इस संदर्भ में अत्यंत गूढ़ है—“हम किसी को दो पैसे दे दें, उसे जब जरूरत हो, किंतु अपनी आंख और कान नहीं दें।” आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अनावश्यक बहुत बोलते हैं और उससे भी अधिक अनावश्यक सुनते हैं। हर व्यक्ति हर किसी की बात सुनने को तत्पर रहता है, चाहे वह बात मन को नीचे खींचने वाली ही क्यों न हो। प्रश्न उठता है—हम क्यों सुनें? हम क्यों देखें? क्या जो भी सामने आए, उसे बिना विवेक के ग्रहण कर लेना ही जीवन है? इंद्रियां ईश्वर की दी हुई अमूल्य निधि हैं। इनका प्रयोग करना हमारा अधिकार ही नहीं, उत्तरदायित्व भी है।

शरीर हमारे कल्याण के संसाधनों का धाम है। आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा—ये केवल भोग के द्वार नहीं हैं, बल्कि साधना के उपकरण हैं। जीवन को परिपूर्णता देने के लिए ये संसाधन हमें जन्म से ही मिले हैं। लेकिन इनका सही उपयोग कौन सिखाए? यही भूमिका माता-पिता और गुरु की है। यदि बचपन में ही यह समझ दे दी जाए कि इंद्रियों का उपयोग संयम और विवेक से करना है, तो आगे चलकर व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। आज की विडंबना यह है कि जिस अनुशासन की अपेक्षा हम बच्चों से करते हैं, वही अनुशासन कई बार अभिभावकों के जीवन में नहीं दिखता। घर में टीवी पर क्या देखा जा रहा है, मोबाइल पर क्या चल रहा है—यदि उसमें ही अशुद्धता है, तो बच्चे से शुद्धता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? शिक्षा केवल उपदेश से नहीं, आचरण से दी जाती है। जब बच्चा देखता है कि उसके माता-पिता भी भद्र को देखते और सुनते हैं, तभी वह उस मार्ग को सहजता से अपनाता है।

इस संसार में रहते हुए ही अनेक महान विभूतियों ने ऋषित्व जीवन प्राप्त किया। उन्होंने जंगल में जाकर नहीं, बल्कि इंद्रियों पर विजय पाकर महानता पाई। यही शिक्षा हमें अपने जीवन में उतारनी है। शरीर को हेय नहीं, पूज्य समझना है, क्योंकि यही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब दृष्टि शुद्ध होगी, श्रवण पवित्र होगा और वाणी संयमित होगी, तब यही शरीर साधना का मंदिर बन जाएगा और जीवन स्वयं एक यज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा।

सनातन संस्कृति, भारत एवं संघ के विरुद्ध गढ़े जा रहे हैं झूठे विमर्श

भारत आज विश्व के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृश्य को बदलने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी देशों के वर्चस्व को पूर्वी देशों से चुनौती मिल रही है, जिसका नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए, अमेरिका के कुछ विघ्नसंतोषी संस्थानों सहित कुछ विकसित देश सनातन हिन्दू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निराधार आरोप लगाकर झूठे विमर्श गढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरअसल, पश्चिमी देशों की समस्या यह है कि वे केवल अपनी आधी अधूरी जानकारी को ही पूर्ण जानकारी मानते हुए अपने विचार तय करते हैं। जबकि, उनके विचार स्पष्टतः सत्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। भारत पर आक्रांताओं एवं अंग्रेजो के शासनकाल में भी सनातन हिंदू संस्कृति एवं भारतीय संस्कारों पर जो विचार गढ़े गए थे, वे पूर्णतः गलत पाए गए थे। जैसे, सनातन संस्कृति के संस्कार रूढ़िवादी हैं एवं यह विज्ञान के धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं, आदि, आदि। उनके द्वारा सनातन संस्कृति के बारे में गढ़े गए विचार पूर्णतः उनके आधे अधूरे ज्ञान पर ही आधारित थे। परंतु, आज सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कार विज्ञान के धरातल पर खरे पाए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के तथाकथित विद्वानों में सनातन हिंदू संस्कृति, भारत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी का पूर्णतः अभाव है। अमेरिका से प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स नामक एक समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में असत्य विचार प्रकट किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित यह आलेख न तो भारत के सामाजिक यथार्थ का परिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, न ही संघ की वैचारिक और संगठनात्मक वास्तविकता को। इस लेख में तथ्यों, आंकड़ों और स्वतंत्र स्रोतों का संतुलित उपयोग नहीं किया गया है और यह लेख पूर्णतः पूर्वाग्रहों पर आधारित दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास एवं संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सम्पन्न किए गए अतुलनीय कार्यों के बारे में इन महानुभावों को कोई जानकारी ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और इसके साथ ही संघ ने देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में शाखाओं की स्थापना करते हुए भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1947 आते आते तो भारत में संघ के स्वयसेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी हो चुकी थी। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा को पार करने की कोशिश की थी तब संघ के स्वयसेवकों ने कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बिना किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर बनाए रखी थी और तब पाकिस्तानी सेना को रोकने हेतु भारतीय सेना के जवानों के साथ संघ के कई स्वयसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथ ही, भारत में विभाजन के समय दंगे भड़कने के दौरान पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदू शरणार्थियों की सहायता के लिए संघ के स्वयसेवकों ने 3,000 से अधिक राहत शिविर भारत में लगाए थे।

कश्मीर के भारत में विलय के समय पाकिस्तान की सेना कबाईलियों के भेष में भारत की सीमा में घुस रही थी, ऐसे में तात्कालीन केंद्र सरकार यह फैसला नहीं ले पा रही थी कि इन परिस्थितियों के बीच क्या किया जाय क्योंकि उस समय कश्मीर के महाराजा श्री हरी सिंह जी भारत में कश्मीर के विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे। इन विकट परिस्थितियों के बीच सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर जी से मदद मांगी और उन्हें कश्मीर में महाराजा श्री हरी सिंह जी से मिलने भेजा। श्री गुरु जी तुरंत कश्मीर गए एवं महाराजा श्री हरी सिंह जी को समझाया और कश्मीर के भारत में विलय सम्बंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए और उसे दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूरे कश्मीर पर कब्जे को विफल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया।

दादरा, नगर हवेली और गोवा को मुक्त कराते हुए भारत में विलय में भी संघ के स्वयसेवकों की प्रमुख भूमिका रही थी। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, 28 जुलाई 1954 को नरोली और फिपारिया को मुक्त कराया गया और फिर राजधानी सिलवासा को मुक्त कराया गया था। संघ के स्वयसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था एवं दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था अतः वर्ष 1955 में संघ के स्वयंसेवकों ने श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में गोवा पहुंच कर गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कई कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनाई गई। हालत बिगड़ते देख अंततः भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और वर्ष 1961 में गोवा को आजादी प्राप्त हुई। इसी प्रकार वर्ष 1962 में भी चीन के साथ भारत के युद्ध के समय संघ के स्वयसेवकों ने भारतीय सेना की भरपूर मदद की थी। संघ के स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ सेना की मदद के लिए सीमा पर पहुंचे थे। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी थी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और ययां तक कि शहीदों के परिवारों की चिंता भी संघ के स्वयसेवकों ने की थी। संघ के इस महान योगदान को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने भी पहचाना था और 26 जनवरी 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को शामिल होने का निमंत्रण दिया था।

अभियान

खुद पर भरोसा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है

रेगिस्तान की तपती रेत, ऊपर से आग बरसाता सूरज और चारों ओर दूर-दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं। ऐसा वातावरण किसी भी मजबूत इंसान के हौसले तोड़ने के लिए काफी होता है। इसी भयावह परिस्थिति में एक व्यक्ति भटकता हुआ अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। उसके पास जो थोड़ा-बहुत खाना-पीना था, वह खत्म हो चुका था। दो दिनों से उसके होंठ सूख चुके थे, गला प्यास से जल रहा था और शरीर जवाब देने लगा था। मन जान चुका था कि अगर अगले कुछ घंटों में पानी नहीं मिला, तो जीवन की डोर टूट जाएगी। फिर भी कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि शायद ईश्वर कोई रास्ता निकाल दे।

रेगिस्तान में भटकते-भटकते उसकी नजर दूर एक झोंपड़ी पर पड़ी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मृगतृष्णा उसे कई बार धोखा दे चुकी थी। कई बार ऐसा लगा था कि सामने पानी है, कोई बस्ती है, लेकिन पास पहुंचते ही सब भ्रम साबित हुआ। इस बार भी मन में संशय था, लेकिन अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। बची-खुची ताकत समेटकर वह झोंपड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे-जैसे वह पास पहुंचता, उम्मीद मजबूत होती जाती। इस बार किस्मत ने साथ दिया—वह कोई भ्रम नहीं, सचमुच एक झोंपड़ी थी।

झोंपड़ी के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वह फिर ठिठक गया। झोंपड़ी वीरान थी, जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही न हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। फिर भी पानी की उम्मीद उसे अंदर खींच ले गई। झोंपड़ी के भीतर उसने जो देखा, उससे उसकी थकी हुई आंखों में फिर से जान आ गई। वहां एक हैंड पंप लगा हुआ था। उस पल उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। प्यास से तड़पता हुआ वह व्यक्ति अचानक नई ऊर्जा से भर गया और तेजी से हैंड पंप चलाने लगा। लेकिन एक झटका उसे फिर हताशा की ओर ले गया—पंप बिल्कुल सूखा था। न पानी की आवाज, न ठंडक का एहसास। बस लोहे की कराहती हुई आवाज।

उसका मन टूट गया। शरीर की सारी ताकत जैसे एक ही पल में खत्म हो गई। उसे लगा कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा, यही उसकी आखिरी मंजिल है। वह वहीं जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर ऊपर गई। झोंपड़ी की छत से एक बोतल बंधी हुई थी। बोतल पानी से भरी हुई थी। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। वह जैसे-तैसे उठकर बोतल तक पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। प्यास इतनी तीव्र थी कि वह उसी पल बोतल खोलकर पानी पी लेना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर बोतल से चिपके एक कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था—“इस पानी का इस्तेमाल हैंड पंप चलाने के लिए करें और वापस बोतल भरकर रखना न भूलें।” यह पढ़ते ही वह व्यक्ति उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसकी जान बचाने के लिए सामने पानी था, दूसरी तरफ एक अजीब सा निर्देश। मन में सवालों की बाढ़ आ गई। अगर उसने पानी हैंड पंप में डाल दिया और पंप नहीं चला तो? अगर जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो तो? तब उसके पास न पानी बचेगा, न कोई और रास्ता। लेकिन अगर लिखा सच हुआ और पंप चल पड़ा तो? क्या पता यह किसी ऐसे इंसान का अनुभव हो, जो पहले यहां आया हो और जिसने मदद के लिए यह व्यवस्था छोड़ी हो।

यह जीवन का सबसे कठिन फैसला था। यह फैसला केवल पानी पीने या न पीने का नहीं था, बल्कि खुद पर भरोसा करने या डर के आगे हार मानने का फैसला था। कुछ पल तक वह जमीन पर बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ सूखे थे और आंखों में मौत का साया मंडरा रहा था। अंत में उसने एक गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह भरोसा करेगा। उसने सोचा, “अगर मैं इस पानी को अभी पी लूं, तो शायद कुछ देर और जी लूं, लेकिन अगर यह पंप सच में काम करता है, तो सिर्फ मेरी नहीं, आने वाले न जाने कितने लोगों की जान बच सकती है।”

कांपते हाथों से उसने बोतल खोली और पूरा पानी हैंड पंप में डाल दिया। फिर उसने आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना की। उसने हैंड पंप चलाना शुरू किया—एक बार, दो बार, तीन बार कुछ नहीं हुआ। दिल बैठने लगा। फिर चौथी बार, पांचवीं बार और अचानक हैंड पंप से ठंडा-ठंडा पानी बहने लगा। वह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। पानी की धार देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भरकर पानी पिया, शरीर में फिर से जान आ गई, दिमाग काम करने लगा और उम्मीद ने फिर से जन्म लिया।

उस व्यक्ति ने केवल अपनी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि जिम्मेदारी भी निभाई। उसने बोतल में फिर से पानी भरा और उसे वापस छत से बांध दिया, जैसा कि कागज में लिखा था। तभी उसकी नजर एक और शीशे की बोतल पर पड़ी। उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा रखा हुआ था, जिस पर रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा, रास्ता याद किया और उस बोतल को भी वहीं वापस रख दिया। इसके बाद उसने अपनी खाली बोतलों में पानी भरा और जीवन की नई उम्मीद के साथ वहां से निकल पड़ा।

कुछ दूर चलने के बाद वह रुका। उसने पीछे मुड़कर झोंपड़ी की ओर देखा। उसके मन में एक विचार आया। वह वापस लौटा, पानी से भरी बोतल पर लगे पुराने कागज को उतारा और उस पर कुछ और लिखने लगा। उसने लिखा—“मेरा यकीन करिए, यह हैंड पंप काम करता है।” यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उस व्यक्ति के अनुभव, साहस और भरोसे की गवाही थे।

यह कहानी केवल रेगिस्तान में भटके एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सब की जिंदगी की कहानी है। हम सभी अपने-अपने जीवन के रेगिस्तान में कभी न कभी भटकते हैं। समस्याएं, असफलताएं, डर और अनिश्चितता हमें घेर लेती हैं। कई बार हमारे सामने भी ऐसी बोतल होती है, जिसमें थोड़ा-सा भरोसा भरा होता है। सवाल यह होता है कि हम उस भरोसे को तुरंत अपने डर की प्यास बुझाने में खर्च कर देंगे या उसे सही जगह लगाकर बड़े समाधान की उम्मीद करेंगे।

अक्सर हम सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। हम वही करते हैं जिसमें तुरंत लाभ दिखे, भले ही वह अस्थायी हो। लेकिन जीवन में असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां हम डर के बावजूद खुद पर भरोसा करते हैं। हैंड पंप चलाने के लिए पानी डालना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उसी फैसले ने उस व्यक्ति की जान बचाई। इसी तरह, जीवन में कई बार हमें अपने डर, आराम और सीमित सोच को दांव पर लगाना पड़ता है।

यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होना चाहिए। भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके जोखिम उठाया जाए, बल्कि यह कि उम्मीद और विवेक के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए। साथ ही, यह भी सिखाती है कि जब हमें कुछ मिलता है, तो उसे केवल अपने तक सीमित न रखें। जैसे उस व्यक्ति ने बोतल फिर से भरकर रखी, वैसे ही हमें भी अपने अनुभव, ज्ञान और संसाधन दूसरों के लिए छोड़ने चाहिए।

अंत में यही कहा जा सकता है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो साधन अपने-आप रास्ता बना लेते हैं। जीवन का हर हैंड पंप तभी चलता है, जब हम उसमें अपने विश्वास का पानी डालते हैं। और जब वह चल पड़ता है, तो न केवल हमारी प्यास बुझती है, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की धार बहने लगती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क जांबुडिया-पानेली : एक विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक विकास का नया केन्द्र

मोरबी से वैश्विक बाजारों तक : वीजीआरसी राजकोट में एडवांस्ड सिरामिक्स में रणनीतिक निवेश के अवसर

गांधीनगर, 31 दिसंबर : जांबुडिया-पानेली में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा विकसित किए गए इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क के लोकार्पण को राज्य के औद्योगिक इतिहास में एक मील के पत्थर समान उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के विजन को साकार करने वाली दिशा में एक सशक्त कदम है। जीआईडीसी इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क गुजरात के उत्पाद क्षेत्र के भविष्य को मजबूत आधार देता है और एक परिवर्तनशील अवसर प्रदान करता है।

जांबुडिया-पानेली में जीआईडीसी का रणनीतिक औद्योगिक विकास

जीआईडीसी द्वारा मोरबी-राजकोट औद्योगिक पट्टे में जांबुडिया-पानेली में एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 1050 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पार्क विश्वविख्यात मोरबी सिरामिक क्लस्टर के निकट होने के कारण मजबूत एवं स्थापित औद्योगिक इकोसिस्टम का पूरा लाभ उठाता है।

मूल्य श्रृंखला में विस्तार तथा औद्योगिक प्रभाव

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की संरचना सिरामिक उद्योग की समग्र मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति को विस्तृत करने के लिए की गई है। पार्क में मुख्यतः टाइल्स तथा सेनेटरी वेयर उत्पादन पर बल दिया जाएगा तथा औद्योगिक एवं एडवांस्ड सिरामिक्स जैसे उच्च मूल्य वाले और विशिष्ट सेगमेंट्स में नए निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह पहल गुजरात को वैश्विक सिरामिक उत्पाद मानचित्र पर और मजबूत स्थान दिलाएगी।

लॉजिस्टिक्स तथा रणनीतिक कनेक्टिविटी

जांबुडिया-पानेली सिरामिक पार्क को उत्तम लॉजिस्टिक्स तथा कनेक्टिविटी का लाभ मिलता है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या 27 से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि मोरबी का निकटस्थ रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा; राजकोट में स्थित हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 70 किलोमीटर तथा मकनसर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो केवल 5 किलोमीटर दूर है। नवलखी (48 किलोमीटर), कंडला (139 किलोमीटर) और मुंद्रा (195 किलोमीटर) जैसे मुख्य बंदरगाहों की निकटता वैश्विक निर्यात के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

बेस्पोक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आधुनिक सुविधाएँ

इस पार्क की विशेषता यह है कि यहाँ उद्योगों की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरूप बेस्पोक इन्फ्रास्ट्रक्चर (विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एस्टेट में कॉमन डिसप्ले सेंटर, एनएबीएल-प्रमाणित प्रयोगशाला से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा नवाचारा को प्रोत्साह देने एवं कार्यबल की कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

उद्योगों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर 30 एमएलडी क्षमता वाली समर्पित जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए एस्टेट में तीन सबस्टेशन हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है; जिनमें दो 66 केवी और एक 220 केवी क्षमता वाले सबस्टेशन होंगे। इसके अतिरिक्त; पर्यावरणीय रूप से दायित्वपूर्ण कामकाज सुनिश्चित करने हेतु ठोस कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – कच्छ एवं सौराष्ट्र : औद्योगिक विकास का सशक्त मंच

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – कच्छ एवं सौराष्ट्र के दौरान राजकोट में क्षेत्र के सिरामिक्स, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स तथा ग्रीन एनर्जी आदि से जुड़े अग्रणी उद्योगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 11 तथा 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होने वाली यह कॉन्फ्रेंस स्थानीय उद्योगों, उद्योग अग्रणियों तथा निवेश भागीदारों के लिए सहयोग एवं वृद्धि के नए अवसरों का सृजन करेगी। प्रतिनिधि जांबुडिया-पानेली सिरामिक पार्क को औद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तथा कौशल विकास के मॉडल के रूप में देख रहे हैं। मोरबी के आसपास उपलब्ध विशाल एवं कुशल मानव संसाधन तथा गुणवत्तायुक्त ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस मजबूत आधार के कारण यह पार्क सिरामिक क्षेत्र में गुणवत्ता तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति का अग्रणी केन्द्र बना है।

सीजीएसटी दफ्तर में रिश्वत का बड़ा खेल उजागर, आईआरएस अधिकारी समेत पांच गिरफ्तार

लखनऊ। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झांसी स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय में फैले रिश्वतखोरी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एक आईआरएस अधिकारी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तलाशी के दौरान 1.60 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, जेवरात और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार यह पूरा मामला जीएसटी चोरी से जुड़े मामलों में निजी कंपनियों को राहत दिलाने और जांच को प्रभावित करने के एवज में मोटी रिश्वत मांगने से जुड़ा है, जिसने कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि झांसी सीजीएसटी में तैनात डिप्टी कमिश्नर आईआरएस प्रभा भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने जीएसटी चोरी के मामलों में कार्रवाई से बचाने और अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले एक निजी फर्म से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस मांग को लेकर शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू की और पुख्ता सबूत जुटाने के बाद जाल बिछाया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पूरे लेनदेन में विभाग के अन्य अधिकारी, एक अधिवक्ता और एक निजी कंपनी का मालिक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

बुधवार को सीबीआई की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 70 लाख रुपये लेते समय सीजीएसटी के अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों के पास से 70 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिससे मामले की पुष्टि हो गई। इसके बाद सीबीआई ने तत्काल आगे की कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, निजी कंपनी के मालिक राजू मंगतानी और बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और रिश्वत की रकम कई किस्तों में वसूली जानी थी।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सभी आरोपितों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जहां से 90 लाख रुपये अतिरिक्त नकद, कीमती जेवरात और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। इन बरामदगियों के साथ ही कुल जब्त नकदी की राशि 1.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच से और भी वित्तीय अनियमितताओं और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस नेटवर्क के तार किसी अन्य शहर या राज्य के सीजीएसटी कार्यालयों से भी जुड़े हुए हैं।

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी गिरफ्तार आरोपितों को मेडिकल परीक्षण के बाद संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही यह भी संकेत दिए गए हैं कि जांच का दायरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और कर चोरी तथा रिश्वतखोरी से जुड़े इस पूरे तंत्र की गहराई से जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ भी कानून अपना काम करेगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, 04 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विशेष किराये पर विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 01 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 26 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09621 अजमेर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 25 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09057/09058 उधना – मंगलुरु स्पेशल (द्विसाप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09057 उधना–मंगलुरु स्पेशल को 28 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु–उधना स्पेशल को 29 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 09059/09060 उधना – खुरदा रोड स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09059 उधना–खुरदा रोड स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09060 खुरदा रोड–उधना स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04828 एवं 09622 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 जनवरी, 2026 से जबकि, ट्रेन संख्या 09057 एवं 09059 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 02 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सरकार ने निर्यातकों के लिए संरचित वैश्विक बाज़ार पहुंच को आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) योजना शुरू की - फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली, 31 दिसंबर 2025- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (एपीएम) के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) योजना शुरू करने का स्वागत किया है और इसे भारत के वैश्विक निर्यात पदचिह्न , खासकर एमएसएमई , पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की फर्मों को मजबूत करने के लिए एक समय पर और रणनीतिक कदम बताया है।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना भारत की निर्यात संवर्धन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। पूर्वानुमानित, अच्छी तरह से नियोजित और परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की एक लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत को पूरा किया है,

जिन्हें अक्सर विदेशी बाजारों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

एमएएस योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर, 2025 को मंज़ूरी दी थी, निर्यात संवर्धन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।

एमएएस के तहत, सरकार खरीदार-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स बायर-सेलर मीट (आरबीएसएम) और प्राथमिकता वाले और उभरते बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच पहलों के माध्यम से खरीदारों से संपर्क में सुधार करना और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है।

श्री रल्हन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का तीन से पांच साल का अग्रिम कैलेंडर प्रदान करने से निर्यातकों और व्यापार निकायों के लिए योजना की निश्चितता में काफी सुधार होगा। एमएसएमई की न्यूनतम 35 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य करना और नए भौगोलिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, भारत के निर्यात विकास को व्यापक बनाने और विविधीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार होगा।

एमएएस ढांचा कार्यक्रम स्तर की वित्तीय सहायता सीमाओं और लागत-साझाकरण अनुपातों को भी तर्कसंगत बनाता है, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बाजारों के लिए तरजीही सहायता दी जाती है। पिछले साल 75 लाख रूपये तक के निर्यात टर्नओवर वाले छोटे निर्यातकों को आंशिक हवाई किराए में मदद मिलेगी, जिससे ग्लोबल इवेंट्स में नए और छोटे निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

इस स्कीम के डिजिटल होने पर ज़ोर देते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि trade.gov.in पोर्टल के ज़रिए प्रक्रियाओं की समग्र डिजिटाइज़ेशन पारदर्शिता, आसानी से पहुंच और तेज़ी से अप्रूवल सुनिश्चित करेगा। अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक, लीड ट्रैकिंग और परिणाम मापने वाले टूल बाज़ार पहुंच के उपायों को असल बिज़नेस नतीजों के साथ जोड़ने में मदद करेंगे।

फियो ने खासकर टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव और सनराइज़ सेक्टर के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन सपोर्ट शुरू करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया और मार्केट इंटेलिजेंस और निर्यातक फॉलो-अप के लिए एडवांस्ड डिजिटल टूल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी स्वागत किया। श्री रल्हन ने कहा कि एमएएस में मज़बूत खरीदार जुड़ाव, डेटा-संचालित पॉलिसी फीडबैक और भारतीय निर्यातकों को ग्लोबल वैल्यू चेन में गहराई से जोड़ने के ज़रिए भारत के निर्यात इकोसिस्टम की नींव बनने की क्षमता है।

फियो ने एमएएस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्यात करने वाले समुदाय के लिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे सुनिश्चित करने के लिए सरकार और सभी हितधारक के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

2026 में भी विकास की रफ्तार नहीं थमेगी, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत

नई दिल्ली। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत आने वाले साल 2026 में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई, स्थिर और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली तथा लगातार बढ़ता निवेश विश्वास ऐसे कारक हैं, जो भारत की विकास यात्रा को निरंतर गति दे रहे हैं। वर्ष 2025 में हासिल हुई तेज आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और बुनियादी ढांचे से लेकर उद्योग, सेवा और वित्तीय क्षेत्रों तक निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नीतिगत प्रयासों के चलते वैश्विक आर्थिक सुस्ती और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में भी दुनिया के लिए एक स्थिर और आकर्षक ग्रोथ इंजन बनी रहेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार नीतिगत कदम उठा रही है। केंद्र सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय बढ़ाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को तेज करने पर है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में बड़े प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इन उपायों से घरेलू मांग मजबूत होगी और विदेशी निवेशकों के लिए भारत और अधिक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा।

आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने 4.18 ट्रिलियन डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता और मजबूत घरेलू बाजार को दर्शाती है। अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों का अनुमान है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो साल 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर में लगातार मजबूती देखी गई है और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को अग्रणी स्थान दिलाती है।

महंगाई के मोर्चे पर भी हालात राहत देने वाले रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति साल 2025 की शुरुआत में 4.26 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो नवंबर तक घटकर 0.71 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई नरमी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार इस गिरावट के प्रमुख कारण रहे। नियंत्रित महंगाई ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को सहारा दिया है और खपत आधारित वृद्धि को मजबूती प्रदान की है। इसके साथ ही सरकार राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को 2022-23 में बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रही है, जिससे जीडीपी गणना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और अधिक सटीक बनाया जा सके।

सुधारों के मोर्चे पर भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। वर्ष 2025 के अंत में जीएसटी दरों में संभावित कटौती और नए श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे कर संरचना सरल होगी, अनुपालन आसान बनेगा और संगठित क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भी बाजार और उद्योग जगत में काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था को और गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और सुधारों को मजबूती प्रदान करने वाले अतिरिक्त उपायों की घोषणा की अपेक्षा की जा रही है।

01 जनवरी 2026 से भावनगर रेलवे मंडल पर नया टाइम टेबल लागू, भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर 01 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। इसमें कुछ ट्रेनों की गति बढ़ाई जा रही है, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस बार भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 04 ट्रेनों को वर्तमान निर्धारित समय से पहले तथा 08 ट्रेनों को वर्तमान निर्धारित समय से विलंब/देरी से चलाया जाएगा। भावनगर मंडल से होकर जाने वाली 17 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, साथ ही यात्रा में लगने वाले समय में 05 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की कमी की गई है। ट्रेनों की गति बढ़ाए जाने के फलस्वरूप यात्री ट्रेनों के परिचालन समय मे कमी आई है। इसका पूरा लाभ यात्रियों को मिलेगा व उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में समय की बचत होगी।

प्रारंभिक स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन नंबर 59228 भावनगर-सुरेन्द्रनगर पैसेन्जर, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 05.10 बजे की बजाय 05.05 बजे प्रस्थान करेगी।

2.ट्रेन नंबर 59234 भावनगर-सुरेन्द्रनगर पैसेन्जर, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 13.40 बजे की बजाय 13.30 बजे प्रस्थान करेगी।

3.ट्रेन नंबर 19209 भावनगर-ओखा दैनिक एक्सप्रेस, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 22.10 बजे की बजाय 22.00 बजे प्रस्थान करेगी।

4.ट्रेन नंबर 59554 बोटाद-गांधीग्राम पैसेन्जर, बोटाद स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 17.10 बजे की बजाय 17.00 बजे प्रस्थान करेगी।

प्रारंभिक स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय से देरी से प्रस्थान करने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन नंबर 16333 वेरावल-तिरूवनंतपुरम सेन्ट्रल एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 06.50 बजे की बजाय 06.55 बजे प्रस्थान करेगी।

2.ट्रेन नंबर 11463 वेरावल-जबलपुर एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 10.05 बजे की बजाय 10.10 बजे प्रस्थान करेगी।

3.ट्रेन नंबर 11465 वेरावल-जबलपुर एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 10.05 बजे की बजाय 10.10 बजे प्रस्थान करेगी।

4.ट्रेन नंबर 26902 वेरावल-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 14.40 बजे की बजाय 14.45 बजे प्रस्थान करेगी।

5.ट्रेन नंबर 19204 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 18.40 बजे की बजाय 19.00 बजे अर्थात् 20 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

6.ट्रेन नंबर 59215 भाणवड-पोरबंदर पैसेन्जर भाणवड स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 21.50 बजे की बजाय 22.40 बजे अर्थात् 50 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

7.ट्रेन नंबर 59555 गांधीग्राम-बोटाद पैसेन्जर गांधीग्राम स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 18.50 बजे की बजाय 19.00 बजे प्रस्थान करेगी।

8.ट्रेन नंबर 59271 बोटाद-भावनगर पैसेन्जर बोटाद स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 15.45 बजे की बजाय 15.50 बजे प्रस्थान करेगी।

उल्लेखनीय है कि भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर पीट लाइन की मरम्मत हेतु चल रहे कार्य की वजह से जो ट्रेनें 25 जनवरी, 2026 तक निरस्त की गई हैं, वे निरस्त हीं रहेंगी तथा उन ट्रेनों पर यह परिवर्तित समय कार्य पूर्ण होने के पश्चात लागू होगा।

सोना वायदा में 1416 रुपये और चांदी वायदा में 14298 रुपये की गिरावटः क्रूड ऑयल वायदा में 26 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 746336.83 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 56524.94 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 689793.44 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 34891 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3533.58 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 45535.32 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 136327 रुपये के भाव पर खूलकर, 136327 रुपये के दिन के उच्च और 135116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 136666 रुपये के पिछले बंद के सामने 1416 रुपये या 1.04 फीसदी लुढ़ककर 135250 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 810 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 110105 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 56 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 13760 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 133586 रुपये के भाव पर खूलकर, 133700 रुपये के दिन के उच्च और 131950 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1544 रुपये या 1.15 फीसदी गिरकर 132430 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 136381 रुपये के भाव पर खूलकर, 136381 रुपये के दिन के उच्च और 133557 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 135031 रुपये के पिछले बंद के सामने 441 रुपये या 0.33 फीसदी गिरकर 134590 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 241400 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 242000 रुपये और नीचे में 232228 रुपये पर पहुंचकर, 251012 रुपये के पिछले बंद के सामने 14298 रुपये या 5.7 फीसदी गिरकर 236714 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 13714 रुपये या 5.43 फीसदी गिरकर 238740 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 13648 रुपये या 5.41 फीसदी घटकर 238802 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 56524.94 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 689793.44 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 45535.32 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34891 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 7842.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 1.95 रुपये या 0.15 फीसदी गिरकर 1280 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 9.5 रुपये या 3.16 फीसदी की तेजी के संग 310 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.9 रुपये या 0.64 फीसदी लुढ़ककर 296.6 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 2.6 रुपये या 1.35 फीसदी की तेजी के संग 195 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3054.73 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5229 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5262 रुपये और नीचे में 5204 रुपये पर पहुंचकर, 26 रुपये या 0.5 फीसदी बढ़कर 5261 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 22 रुपये या 0.42 फीसदी की मजबूती के साथ 5261 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 360 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 360 रुपये और नीचे में 342 रुपये पर पहुंचकर, 357.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 14.3 रुपये या 4 फीसदी गिरकर 343.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 14.4 रुपये या 4.02 फीसदी की गिरावट के साथ 343.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 1025 रुपये पर खूलकर, 21 रुपये या 2.06 फीसदी औंधकर 1000 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 17644.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 27890.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 7141.71 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 315.66 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 24.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 360.51 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 388.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2649.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19145 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 91703 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 25699 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 416435 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47103 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17348 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40581 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 105233 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19770 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38094 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 35000 पॉइंट पर खूलकर, 35252 के उच्च और 34736 के नीचले स्तर को छूकर, 918 पॉइंट घटकर 34891 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 11.5 रुपये की बढ़त के साथ 160.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.45 रुपये की गिरावट के साथ 25.85 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 296.5 रुपये की गिरावट के साथ 53 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 249000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7892.5 रुपये की गिरावट के साथ 12623 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 24.66 रुपये की गिरावट के साथ 73.1 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 75 पैसे की नरमी के साथ 9.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 9.5 रुपये की गिरावट के साथ 108.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.15 रुपये की बढ़त के साथ 30.65 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 276.5 रुपये की बढ़त के साथ 535.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 899 रुपये की बढ़त के साथ 3180 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 28.05 रुपये की बढ़त के साथ 89.72 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 25 पैसे की नरमी के साथ 9.5 रुपये हुआ।

‘स्वागत’ : पिछले 22 वर्षों से गुजरात के नागरिकों का सरकार में विश्वास दृढ़ कर रहा प्लेटफॉर्म

22 वर्षों में ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म से 99 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निपटान किया गया

▸▸ निर्धारित समयसीमा में नागरिकों की समस्याओं के उचित निवारण के लिए ‘स्वागत 2.0’ ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति लागू

▸▸ आवेदनों के समय पर निराकरण के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, अधिकारियों के परफॉर्मेंस के परीक्षण के लिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाया गया

गांधीनगर : नागरिकों तथा सरकार के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी में विद्यमान क्षमता का अधिकतम् उपयोग कर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2003 को स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (‘SWAGAT’ – ‘स्वागत’) कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरल; परंतु सशक्त था कि नागरिक भय, विलंब और प्रक्रियागत अवरोधों के बिना सरकार के उच्चतम् स्तरों के समक्ष अपनी शिकायतें सीधे ही प्रस्तुत कर सकें। ‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का दायरा जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर तक विस्तृत हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस पहल को आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रभावशाली ढंग से संचालित कर रहे हैं। वर्ष 2003 से लेकर आज 22 वर्षों से ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म गुजरात के नागरिकों का राज्य सरकार में विश्वास दृढ़ कर रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पिछले 22 वर्षों में इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुए 99.10 प्रतिशत आवेदनों का सकारात्मक निपटान किया गया है।

कैसे काम करती है ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति ?

आधुनिक ‘स्वागत’ सिस्टम की संरचना एक ऑटोमैटिक एस्केलेशन फ्रेमवर्क के आसपास की गई है, जो सुनिश्चित करता है कि शिकायतें किसी भी स्तर पर अवरुद्ध न हो जाएँ। ‘स्वागत 2.0’ में नागरिकों की समस्याओं का निश्चित समयसीमा में गुणात्मक निवारण लाने के लिए निपटान की समयसीमा निर्धारित की गई है। आवेदक की प्रस्तुति/शिकायत उस अधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाती है, जिसकी उस प्रस्तुति/शिकायत के निवारण की सीधी जिम्मेदारी है। आवेदक की प्रस्तुति के प्रति सम्बद्ध अधिकारी को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। आवेदकों को भी पंजीकरण से लेकर अंतिम निवारण तक के प्रत्येक चरण पर उनकी शिकायत की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा अवगत कराया जाता है। यदि सम्बद्ध अधिकारी द्वारा निर्धारित समयसीमा में शिकायत का निवारण न किया जाए, तो वह शिकायत समयसीमा पूर्ण होने के बाद ऑटोमैटिक उसके एक लेवल ऊपर के अधिकारी के लॉगिन में ऑटो एस्केलेट होती है। इसके बाद उस उच्च अधिकारी को शिकायत का निवारण करना होता है। उच्चाधिकारी द्वारा शिकायत निवारण करना अनिवार्य है। प्रस्तुति का संतोषजनक तथा उचित ढंग से निवारण हुआ होने संबंधी वेरिफिकेशन होने के बाद ही प्रस्तुति का अंतिम निपटान हुआ माना जाता है। इसके अतिरिक्त; आवेदक अपनी शिकायत को लेकर हुई कार्यवाही से संतुष्ट न हों, तो वे फीडबैक देकर शिकायत को एक लेवल ऊपर के अधिकारी को एस्केलेट भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा भी इन आवेदनों की सघन निगरानी की जाती है।

‘स्वागत’ 2.0 ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वागत’ को एक सक्रिय एवं लोक केन्द्रित प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था। अब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समय तथा टेक्नोलॉजी के साथ ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 25 दिसंबर, 2024 को राज्य के सभी जिलों एवं सभी विभागों में ‘स्वागत 2.0’ ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति लागू की गई है और साथ ही ‘स्वागत’ ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति 25 दिसंबर, 2023 को ‘सुशासन दिवस’ के उपलक्ष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्व एवं पंचायत विभाग तथा पाटण व खेडा जिलों में लागू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद कुल 21,540 आवेदनों में से 90 प्रतिशत आवेदनों का समयसीमा में सकारात्मक समाधान किया गया। इस प्रकार; पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने के बाद आगामी सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर, 2024 को ‘स्वागत 2.0’ सभी जिलों में लॉन्च किया गया।

शिकायतों के समय पर निवारण के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का समय पर निवारण लाने के उम्दा उद्देश्य से विभिन्न मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा; अधिकारियों के परफॉर्मेंस के परीक्षण के लिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जिसके आधार पर यह जानकारी मिलती है कि किस जिले में किस प्रकार की शिकायतें अधिक संख्या में आती हैं और राज्य के विभिन्न जिलों से मिलने वाली शिकायतों के अनुसार किस तरह के नीतिगत परिवर्तनों की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि ‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से कई नीतिगत निर्णय किए गए हैं; जिनमें मुख्यतः किसानोन्मुखी, भूमि अधिग्रहण, विद्यार्थी-उन्मुखी, गौचर भूमि अतिक्रमण, री-सर्वे, पुलिस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से मोडदर गाँव के 118 किसानों की समस्या हुई समाप्त

पोरबंदर जिले की कुतियाणा तहसील के मोडदर गाँव में ‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ। मोडदर गाँव से पसवारी के बीच सुखभादर नदी पर पुल नहीं होने के कारण किसानों को पिछले 40 वर्षों से अपने खेत में 15 किलोमीटर घूमकर पहुँचना पड़ता था। इस संबंध में आवेदक श्री लखमणभाई नवघणभाई मोडेदरा ने तहसील एवं जिला स्तर पर शिकायत की और इसके बाद उनकी समस्या राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम तक पहुँची। आवेदक ने पुल न होने के कारण 118 किसानों को 3600 बीघा भूमि की खेती के रोजमर्रा के कार्य में पड़ने वाली कठिनाइयाँ प्रस्तुत की थीं। उनकी प्रस्तुति सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने पुल तथा सड़क के कार्य तत्काल पूर्ण करने के लिए सड़क एवं भवन सचिव तथा पोरबंदल जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप मोडदर-पसवारी के बीच 9 करोड़ रुपए की लागत से माइनर ब्रिज, क्लवर्ट और तीन किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा।

पिछले 2 वर्ष में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने ली ‘स्वागत’ इकाई की मुलाकात

‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम को समझने के लिए भारत सरकार के सचिव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि जैसे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालयों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा ‘स्वागत’ इकाई की मुलाकात ली गई है। उन्होंने अपने राज्य में भी इस प्रकार की सुविधा लागू करने के बारे में जानकारी हासिल की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण जन हितकारी निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य की सभी 34 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान सम्बद्ध जिलों के स्थानीय महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए आवंटित करने के दिशानिर्देश दिए हैं।

राज्य में विधायकों को विकेन्द्रित जिला योजना कार्यक्रम अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान

▸▸ 34 जिलों की जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का वार्षिक विवेकाधीन अनुदान स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा

आवंटित करने की परंपरा है।

मुख्यमंत्री के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को वेग मिले और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके; इस आशय से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी विवेकाधीन अनुदान आवंटित करने की प्रस्तुतियाँ-मांग की थीं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों पर सकारात्मक तथा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए यह एक करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान जिला पंचायत अध्यक्ष को आवंटित करने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को दिया है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहतर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MoU विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सैलरी और पेंशन खाते के माध्यम से सुविधाजनक वित्तीय सेवाओं और आकर्षक लाभ प्रदान करता है।

MoU पर हस्ताक्षर निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए:

पश्चिम रेलवे: श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक एवं श्री सिद्धार्थ, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, अहमदाबाद मंडल

पंजाब नेशनल बैंक: श्री विनिश चावला, क्षेत्रीय प्रबंधक गुजरात, श्री जगदीश गुप्ता, AGM मार्केटिंग और श्री कुणाल चटर्जी, मुख्य प्रबंधक

सैलरी और पेंशन खातों की प्रमुख विशेषताएँ:

सैलरी खाता:

▸▸ टर्म इंश्योरेंस: 10 लाख (NEO वेरिएंट को छोड़कर)

▸▸ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (PAI): 100–125 लाख

▸▸ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (AAI): 200–250 लाख

▸▸ लॉकर किराए पर 100% तक छूट

▸▸ विशेष डेबिट कार्ड ऑफ़र

▸▸ परिवार के सदस्यों के लिए शून्य शेष खाते

पेंशन खाता:

▸▸ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (PAI): 15–30 लाख

▸▸ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (AAI): 30–60 लाख

▸▸ हॉस्पी-कैश: 30,000–90,000

▸▸ रिटेल लोन पर ब्याज दर में छूट

▸▸ वार्षिक स्वास्थ्य जांच और असीमित टेली-कंसल्टेशन

▸▸ डिजिटल पर्सनल/पेंशन लोन सुविधा

यह सहयोग पश्चिम रेलवे की कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे उन्हें आधुनिक, सुविधाजनक और वित्तीय रूप से लाभकारी सेवाएँ उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वनवासी विद्यार्थियों के प्रति अनूठी संवेदना

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वनवासी विद्यार्थियों के प्रति संवेदना दिखाते हुए विशेष समय निकालकर बुधवार को गांधीनगर में डांग के बच्चों के साथ मुलाकात की।

डांग जिले के मालेगाम के विद्यालय के शिक्षक सहित 150 से अधिक विद्यार्थी शैक्षणिक यात्रा के दौरान जब गांधीनगर आए, तब मुख्यमंत्री के साथ उनकी यह सहज मुलाकात आदिजाति विद्यार्थियों के अविस्मरणीय स्मृति बन गई।

मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से उन्हें पढ़ाई के लिए मिल रही अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

सांसद श्री गोविंदभाई धोळकिया की ट्रस्टीशिप अंतर्गत संचालित प्रयोशा प्रतिष्ठान द्वारा डांग जिले के मालेगाम में वनवासी विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण शिक्षा तथा विकास का अनूठा सेवायज्ञ चल रहा है।

प्रयोशा प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2002 से शुरू हुए संतोकबा धोळकिया विद्या

▸▸ मुख्यमंत्री ने विशेष समय देकर डांग के वनवासी बच्चों के साथ संवाद-मुलाकात की

▸▸ डांग जिले के मालेगाम के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात बनी अविस्मरणीय स्मृति

मंदिर (निवासी शाला) में डांग जिले के 142 सुदूरवर्ती गाँवों के 400 से अधिक बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

इस विद्यालय में पढ़कर इस वर्ष 1 विद्यार्थी आईआईटी-दिल्ली तथा 2 विद्यार्थी आईआईटी-रुड़की व गोवा में हैं। पूर्व में इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले 182 विद्यार्थी इंजीनियर, 22 विद्यार्थी डॉक्टर, 36 विद्यार्थी शिक्षक बने हैं और लगभग 65 विद्यार्थियों ने पैरामेडिकल की शिक्षा प्राप्त की है। मुख्यमंत्री इस विवरण से भी प्रभावित हुए।

इस अवसर पर केबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, संस्था के अग्रणी श्री पी. पी. स्वामी तथा विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।

गुजरात के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध सज्ज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स का गठन

▸▸ आधुनिक एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से संभावित साइबर खतरे के विरुद्ध राज्य सरकार की पूर्व तैयारी

▸▸ राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर में साइबर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा के साथ रणनीतिक रोडमैप तैयार किया जाएगा

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध सज्ज करने के लिए कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स राज्य

के ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा संबंधी जरूरी कार्य, प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा कर रोडमैप प्रस्तुत करेगी। राज्य की 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में अब स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड तथा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) जैसे आधुनिक सिस्टम्स शामिल किए गए होने के कारण ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर में साइबर हमलों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग (ईपीडी) द्वारा 11 सदस्यीय कोर कमिटी तथा 19 सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति तथा उसकी घटनाओं के प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त; उसमें आवश्यक सुधार तथा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण करने के लिए रोडमैप भी प्रस्तुत करेगी। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी भी की जाएगी और साइबर ड्रिल तथा प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय व राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध चाकचौबंद बनाने के लिए एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

वार्षिक राउंड अप - पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मण्डल 2025

उपलब्धियों, परिचालन उत्कृष्टता और विकास का एक ऐतिहासिक वर्ष,अहमदाबाद मंडल को भारतीय रेलवे स्तर पर नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) में 4th स्थान प्राप्त हुआ

कैलेंडर वर्ष 2025 पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य में एक ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण वर्ष के रूप में उभरकर सामने आया है। इस वर्ष रेल अवसंरचना के विस्तार, सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में संपर्क सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक विकास को गति देने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के माध्यम से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल ने विकास की एक नई गाथा लिखी है।

माल लदान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने वर्ष 2025–26 में अब तक माल ढुलाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सशक्त प्रदर्शन किया है। 30 दिसंबर तक प्रदर्शन के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2024–25 की तुलना में समग्र रूप से सुधार दर्ज किया गया है।

▸▸ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 26000 वैगन की अधिक लोडिंग की गई।

▸▸ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 3889 रैक की अधिक लोडिंग की गई।

▸▸ समयपालन (Punctuality) में अहमदाबाद मण्डल भारतीय रेलवे पर 10 में 8वें स्थान पर रहा।जिसकी समयपालनता 93.93% रही।

▸▸ अहमदाबाद मण्डल ने पहली बार रिकॉर्ड कंटेनर लोडिंग पिछली साल से 13.11% अधिक हुई।

▸▸ खाद की लोडिंग पिछली साल की तुलना में इस वर्ष 19.11% अधिक रही।

▸▸ नमक की लोडिंग पिछली साल की तुलना में इस वर्ष 20.34% अधिक रही।

▸▸ इसी प्रकार, कुल वहन भार 3,53,003 मिलियन टन से बढ़कर 3,86,497 मिलियन टन हो गया, जिसमें लगभग 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र रूप से, ये आंकड़े वर्ष 2025–26 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में परिचालन दक्षता एवं प्रदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाते हैं।

राजस्व प्राप्ति

▸▸ अहमदाबाद मंडल को भारतीय रेलवे स्तर पर नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) में 4th स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि को देखते हुए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के लिए पश्चिम रेलवे को नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) शील्ड घोषित की गई है जो माननीय रेलमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाएगी।

▸▸ अहमदाबाद मंडल को माल लदान में 7 वां प्राप्त हुआ है।

▸▸ पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025) राजस्व अर्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में मंडल के विभिन्न राजस्व स्रोतों में सतत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

▸▸ यात्री राजस्व में अहमदाबाद मंडल ने 6.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1247.31 करोड़ से 1326.87 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। इसी अवधि में यात्रियों की संख्या भी 9.14 प्रतिशत बढ़कर 274.80 लाख से 299.92 लाख हो गई।

▸▸ माल ढुलाई क्षेत्र में मंडल का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा। माल राजस्व में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4856.85 करोड़ से बढ़कर 5193.95 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। पार्सल राजस्व भी 1.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 56.15 करोड़ से 56.76 करोड़ तक पहुँचा।

▸▸ गैर-किराया राजस्व में उल्लेखनीय 86.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 5.82 करोड़ से बढ़कर 10.84 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त टिकट जाँच से होने वाली आय में 54.93 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 14.91 करोड़ से बढ़कर 23.10 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के 16 स्टेशनों असारवा, विरामगाम, ध्रांगध्रा, पालनपुर, महेसाणा, पाटन, कालोल, मणिनगर, सिद्धपुर, चांदलोड़िया, वटवा, हिम्मतनगर, उंझा, भिलडी एवं भचाऊ को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

▸▸ सामाखियाली स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22.05.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत स्टेशन के रूप में किया गया।

▸▸ सभी 16 स्टेशनों पर कुल 515.03 करोड़ की लागत से सॉफ्ट अपग्रेडेशन कार्य प्रगति पर हैं।

▸▸ सॉफ्ट अपग्रेडेशन कार्यों में स्टेशन फसाड एवं परिभ्रमण क्षेत्रों का सुधार, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर एवं बैठने की सुविधाओं का विकास, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (FOB) तथा कोच गाइडेंस सिस्टम की व्यवस्था शामिल है।

▸▸ इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन-अनुकूल उन्नत शौचालय, उन्नत पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, संकेतक (साइनेज), हरित सौंदर्यीकरण, रिटायरिंग रूम, डॉर्मिटरी तथा उन्नत टिकटिंग एवं सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।

▸▸ प्रमुख पुनर्विकास (Major Upgradation) कार्य के अंतर्गत अहमदाबाद स्टेशन पर 2,379.00 करोड़, साबरमती बीजी एवं साबरमती जंक्शन पर संयुक्त रूप से 334.92 करोड़ तथा न्यू भुज स्टेशन पर 202.86 करोड़ की लागत से कार्य प्रगति पर हैं।

नई रेल लाइन/ गेज परिवर्तन

▸▸ आंबलियासन–विजापुर-मोटी आदराज रेलवे लाइन 82 किमी का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह रेलवे लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है।

▸▸ हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा रेलखंड (लगभग 55 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह सेक्शन यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है।

▸▸ कलोल-कडी-कटोसन रोड रेल लाइन का गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण (38 किमी), जो गांधीनगर एवं महेसाणा जिलों को कवर करता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा।

▸▸ महेसाणा–पालनपुर रेल खंड का दोहरीकरण (65.10 किमी), जो बनासकांठा, पाटन एवं महेसाणा जिलों को कवर करता है, दिल्ली–अहमदाबाद राजधानी मार्ग पर शेष अंतिम सिंगल लाइन अंतर को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा।

▸▸ बेचराजी–रणुज रेल खंड का गेज परिवर्तन (40 किमी), जो महेसाणा, पाटन एवं अहमदाबाद के जिलों को कवर करता है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप किया गया।

▸▸ साबरमती–बोटाद रेल खंड का विद्युतीकरण (106 किमी) पूरा होने के साथ ही गुजरात में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित हुआ।

▸▸ सामाख्याली-गांधीधाम-आदिपुर लाइन का चौहरिकरण (63.67 किमी) का कार्य प्रगति पर है।

▸▸ अहमदाबाद बाईपास के हिस्से के रूप में बारेजड़ी नांदेज (गेरतपुर) और साणंद के बीच 38.20 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। बारेजड़ी नांदेज और साणंद के बीच इस चौथी लाइन का निर्माण इन क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा।

रोड अंडर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण

2025–26 के दौरान पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात राज्य में 15 रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर उनके स्थान पर 12 रोड अंडर ब्रिज और 3 रोड ओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण किया गया। पूर्ण किए गए रोड ओवर ब्रिज (ROB) रोड अंडर ब्रिज (RUB) एवं सबवे कार्यों में विरामगाम–सामाखियाली, अहमदाबाद–पालनपुर, पालनपुर–सामाखियाली, मेहसाणा–पाटन-भिलड़ी तथा खोडियार–गांधीनगर जैसे रेलखंडों में अनेक समपार फाटकों का उन्मूलन आरयूबी/आरओबी के निर्माण द्वारा किया गया, जिनमें अधिकांश में कवरड अप्रोच भी प्रदान की गई। अधिकांश कार्य जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच पूर्ण रूप से पूरे किए गए, ये परियोजनाएँ मेहसाणा, गांधीनगर, कच्छ, सुरेन्द्रनगर एवं बनासकांठा जैसे जिलों में फैली हुई हैं, जिससे सड़क-रेल संपर्क और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नई ट्रेन सेवा

▸▸ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 मई, 2025 को वेरावल-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

▸▸ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त, 2025 को गुजरात का दौरा किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी दो महत्वपूर्ण नई रेल सेवाओं कटोसन रोड और साबरमती के बीच पहली मेमू ट्रेन सेवा तथा बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी को अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

संरक्षा

▸▸ अहमदाबाद मंडल में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 82.57 किमी ट्रैक का नवीनीकरण किया गया।

▸▸ यार्ड में अवरोधों को हटाया गया ताकि ट्रेनों का संचालन बाधारहित हो सके।

▸▸ 205 किमी लंबाई में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का निर्माण किया गया ताकि ट्रैक की सुरक्षा और बढ़ाई जा सके।

▸▸ पलनपुर–समाख्याली खंड में 6 स्थायी गति प्रतिबंधों को हटाया गया, जिससे ट्रेन संचालन और अधिक सुचारू हुआ।

▸▸ 20 पुलों की मजबूतीकरण कार्य पूरे किए गए ताकि संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

▸▸ 15 रेल फाटक हटाए गए और उनकी जगह रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हुआ और यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ी।